

वैश्विक खाद्य नियामक परिदृश्य को नई दिशा देता वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023

भारत की अगुआई पर विश्व का पहला खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन दिल्ली में संपन्नभारत , की जमकर हुई सराहना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2023: वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन (जीएफआरएस) 2023 ने अधिक मजबूत खाद्य सुरक्षा और नियामक पारिस्थितिकी तंत्र का मार्ग प्रशस्त किया है। इस अभूतपूर्व पहल ने विश्व की खाद्य सुरक्षा प्रणालियों को बदलने और मजबूत करने की अपनी क्षमता के लिए वैश्विक प्रशंसा प्राप्त की है। सत्रों की चर्चा और परिणामों ने नियामक चुनौतियों से निपटने और दुनिया भर में उपभोक्ताओं की भलाई सुनिश्चित करने में सामूहिक कार्रवाई के लिए एक मजबूत नींव रखी है। शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन (जीएफआरएस) 2023 संपन्न हुआ।

शिखर सम्मेलन का पहला तकनीकी सत्र विभिन्न देशों में खाद्य नियामक प्रणालियों, खाद्य पदार्थों से जुड़े विभिन्न जोखिमों को कम करने के लिए खाद्य नियामकों द्वारा अपनाई गई प्रमुख रणनीतियों, विश्व स्तर पर नियामकों के सामने आने वाली चुनौतियों और एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण के माध्यम से खाद्य मूल्य श्रृंखला में खाद्य सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने पर दृष्टिकोण के आदान-प्रदान पर केंद्रित था। डॉ वी के पॉल, सदस्य, नीति आयोग, भारत ने उद्घाटन सत्र के दौरान विशेष भाषण दिया। उन्होंने प्रभावी खाद्य सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली के लिए राष्ट्रीय नियामक ढांचे के महत्व पर विचार-विमर्श किया। डॉ. पॉल ने कहा, "उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने और वैश्विक खाद्य नियंत्रण प्रणाली में सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए मानकों और विनियमों को स्थापित करने और लागू करने में सामंजस्यपूर्ण वैश्विक नियामक व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।"

कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के उपाध्यक्ष श्री राज राजशेखर ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों के समाधान के लिए कोडेक्स द्वारा की गई पहल पर जोर दिया। पहले वैश्विक नियामक शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए एफएसएसएआई के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, "इस मंच ने विभिन्न देशों के विशेषज्ञों के विचारों को आदान-प्रदान का एक मंच दिया है जो खाद्य सुरक्षा के लिए एक वैश्विक मॉडल विकसित करने में मदद कर सकता है"। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव, श्री राजेश कुमार सिंह ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और खाद्य सुरक्षा से समझौता किए बिना सरल नियमों और छोटे अपराधों को अपराधमुक्त कर खाद्य उद्योग के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

प्रोफेसर सुसान जेब, अध्यक्ष, खाद्य मानक एजेंसी, यूके और सुश्री इसाबेल लैबर्ज, वरिष्ठ निदेशक और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कनाडा ने मानकों की स्थापना और गुणवत्ता आश्वासन में नवाचारों और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने में आधुनिक खाद्य नियमों की भूमिका पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। न्यूजीलैंड की माननीय खाद्य सुरक्षा मंत्री, सुश्री राचेल ब्रोकिंग ने दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा पर अधिक जोर देते हुए प्रतिभागियों को वर्चुअली संबोधित किया। स्वास्थ्य और

परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव श्री एस. गोपालकृष्णन ने एफएसएसएआई द्वारा अपनाई जा रही नियामक प्रणाली प्रस्तुत की, जिसने पैनल चर्चा के लिए एक मंच तैयार किया।

उद्घाटन सत्र के बाद 'ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क' पर एक पैनल चर्चा हुई, जिसमें ब्राजील, भूटान, चिली, इथियोपिया, मॉरीशस, मोजाम्बिक, अमेरिका और न्यूजीलैंड सहित आठ अलग-अलग देशों के पैनलिस्ट शामिल हुए। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव श्री संजीव चोपड़ा द्वारा संचालित इस सत्र के दौरान विभिन्न देशों के अपने अनुभवों और सफल पहलों को साझा किया गया और दूसरों को भी इसी तरह के दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। नियामक प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक खाद्य नियामकों के बीच सहयोग और सहयोग के महत्व पर चर्चा हुई। विशेष रूप से, उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए नियामक मानकों को सुसंगत बनाने पर जोर दिया गया। सर्वोत्तम प्रथाओं और सफलता की कहानियों को विभिन्न देशों द्वारा साझा किया गया, जिन्हें अन्य देशों द्वारा अपनी खाद्य नियामक प्रणाली को मजबूत करने के लिए अपनाने की क्षमता है। चर्चा नियामक मानकों को सुसंगत बनाने और नियामक प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने, उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वैश्विक खाद्य नियामकों के बीच सहयोग और सहयोग के संभावित अवसरों की खोज पर भी केंद्रित थी। पैनल ने सुरक्षा मापदंडों पर जोर देने के साथ मजबूत राष्ट्रीय खाद्य नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए कई एजेंसियों/हितधारकों के बीच सहयोग की रणनीतियों का भी सुझाव दिया। विचार-विमर्श में किसी भी नए विकास या मौजूदा खाद्य विनियमन में संशोधन करते समय सभी हितधारकों की भागीदारी पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

दूसरे तकनीकी सत्र, 'एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर): चुनौतियां और समाधान' में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के आसपास की जटिलताओं पर चर्चा की गई। चर्चा संभावित समाधानों, विश्व स्तर पर एएमआर का मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, सहयोगात्मक प्रयासों, प्रभावी नीतियों और एएमआर मुद्दों के समाधान के लिए एक वैश्विक टास्क फोर्स की स्थापना पर केंद्रित थी। संदर्भ स्थापित करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री लव अग्रवाल ने एएमआर पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) की भूमिका पर जोर देते हुए एएमआर की चिंताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि सभी देशों को वन हेल्थ दृष्टिकोण के साथ एनएपी को अपनाना चाहिए और एएमआर के अंतर-क्षेत्रीय मुद्दे से निपटने के लिए सहयोग महत्वपूर्ण है। डॉ. श्रीधर धरमपुरी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा और पोषण अधिकारी, एफएओ क्षेत्रीय कार्यालय, एशिया और प्रशांत क्षेत्र, बैंकॉक और डॉ. इमैनुएल कबाली, एएमआर परियोजना समन्वय और तकनीकी सहायता सलाहकार/वैश्विक परियोजना समन्वयक, एफएओ, रोम ने भी सभा को संबोधित करते हुए उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके खाद्य सुरक्षा और एंटीबायोटिक दवाओं के विकल्पों के महत्व पर जोर दिया। एएमआर पर पैनल चर्चा का उद्देश्य आमंत्रित देशों और संगठनों द्वारा साझा किए गए हितधारक परामर्श और अनुभवों के माध्यम से ज्ञान को बढ़ाना है। चर्चाओं ने एएमआर पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) और आगामी एनएपी-एएमआर 2 से प्राप्त अंतर्दृष्टि का लाभ उठाते हुए एएमआर को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए संभावित नीतिगत सिफारिशों को तैयार करने में सक्षम बनाया। एएमआर से व्यापक रूप से निपटने के लिए अन्य देशों को अपने एनएपी विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चर्चा का मुख्य केंद्र बन गया। सत्र में एएमआर से सामूहिक रूप से निपटने के लिए खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईई) जैसे नियामकों और संगठनों के बीच बढ़ती नेटवर्किंग, सहयोग और साझेदारी के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। चर्चा के एक अनिवार्य पहलू के रूप में, नैनोटेक्नोलॉजी और अन्य नवीन दृष्टिकोणों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के

माध्यम से एंटीबायोटिक दवाओं के विकल्प तलाशने पर जोर दिया गया।

उपभोक्ता विश्वास के निर्माण में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में खाद्य सुरक्षा पर जोर देने की बात कही गई। उन्होंने यह भी कहा कि मजबूत मानक निर्धारण के महत्वपूर्ण पहलुओं में एक स्पष्ट परिचालन विनियमन प्रबंधन, अच्छी तरह से प्रलेखित खाद्य सुरक्षा प्रबंधन और प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सुरक्षित और पौष्टिक भोजन हर किसी के लिए सुलभ होना चाहिए, चाहे वे कहीं भी रहें।

संदर्भ स्थापित करते हुए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) की सचिव सुश्री अनीता प्रवीण ने उल्लेख किया कि भोजन के संपर्क में आने वाली कोई भी चीज सुरक्षित होनी चाहिए। उन्होंने विज्ञान आधारित मानकों को तैयार करने के महत्व पर प्रकाश डाला लेकिन यह भी बताया कि मानकों की समय-समय पर समीक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सुश्री प्रवीण ने कहा, यह मजबूत प्रवर्तन और क्षमता निर्माण कार्यक्रम है जो एक मजबूत खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मदद करता है।

अपने विशेष संबोधन में, आयुष मंत्रालय के सचिव श्री राजेश कोटेचा ने पारंपरिक दवाओं के रूप में वनस्पति के उपयोग पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। उन्होंने यह भी कहा कि वनस्पति विज्ञान पहले से ही उच्च मांग में है, उपभोक्ता उन्हें पारंपरिक तैयारियों में शामिल कर रहे हैं। इसलिए, उन्होंने इस क्षेत्र में एक मजबूत विनियमन की आवश्यकता पर बल दिया।

मजबूत नियामक मानकों की स्थापना के महत्व पर विचार-विमर्श जारी रखते हुए, डॉ. शशांक जोशी द्वारा संचालित 'हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स' पर एक सत्र में इन उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग पर चर्चा की गई। इस मांग को स्वास्थ्य और कल्याण पर बढ़ते जोर से बढ़ावा मिला है, खासकर कोविड के बाद के युग में। सत्र के दौरान, विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य पूरक और न्यूट्रास्यूटिकल्स के जिम्मेदार और सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नियामक ढांचे, वैज्ञानिक अनुसंधान और उत्पाद गुणवत्ता आश्वासन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। चर्चा में कोडेक्स द्वारा पोषक तत्व संदर्भ मूल्यों (एनआरवी) पर तैयार किए जा रहे दिशानिर्देशों और स्वास्थ्य पूरकों के लिए उनकी प्रयोज्यता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। पैनल ने गैर-चीनी मिठास (एनएसएस) के प्रतिकूल प्रभाव पर भी विचार-विमर्श किया और मानव स्वास्थ्य पर एनएसएस की खपत के प्रतिकूल प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए अध्ययन आयोजित करने का सुझाव दिया। चर्चा प्रोबायोटिक्स के उभरते नए प्रकारों के जोखिम मूल्यांकन और नए खाद्य उत्पादों को विकसित करने के लिए आयुर्वेद की समृद्ध पारंपरिक विरासत को फिर से खोजने और पुनः उपयोग करने के इर्द-गिर्द घूमती रही।

'संदूषक और अवशेष - जोखिम न्यूनीकरण - नियामक हस्तक्षेप' शीर्षक वाले एक अन्य सत्र में भोजन में रासायनिक संदूषकों और कीटनाशक अवशेषों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ खाद्य सुरक्षा मानकों को सुसंगत बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। संदूषकों और अवशेषों के लिए सुरक्षा सीमाएं स्थापित करने, अनुपालन सुनिश्चित करने और जैविक खतरों को रोकने के लिए शमन रणनीतियों को नियोजित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। पैनल ने उभरते संदूषकों और अवशेषों के लिए रणनीतियों की योजना बनाने के लिए डेटा संग्रह के लिए राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाओं के सर्वोत्तम संभव उपयोग का सुझाव दिया। चर्चाओं से जो एक महत्वपूर्ण बिंदु उभरा वह प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवशेषों के लिए अधिकतम अवशिष्ट सीमा (एमआरएल) और संदूषकों के लिए अधिकतम सीमा (एमएल) तय करने के लिए प्रसंस्करण कारकों के निर्धारण पर था। पैनल ने सहक्रियात्मक गुणों को समझने और विभिन्न देशों के बीच अवशेषों और संदूषकों के लिए एमआरएल और एमएल पर निगरानी और निगरानी डेटा के

आदान-प्रदान के लिए विभिन्न कीटनाशक फॉर्मूलेशन के संयोजन के बारे में डेटा उत्पादन के महत्व पर भी चर्चा की।

'जैविक खाद्य पदार्थ' पर पैनल चर्चा जैविक खाद्य क्षेत्र को मजबूत करने और जैविक सिद्धांतों के आधार पर टिकाऊ कृषि प्रणालियों को अपनाने पर केंद्रित थी। वक्ताओं ने जैविक खाद्य पदार्थों और उनकी प्रामाणिकता के बारे में जागरूकता पैदा करने, बाजार के रुझानों का पता लगाने और वैश्विक स्तर पर जैविक उत्पादों के लिए बाजार पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए नीतिगत सिफारिशों की पहचान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। जैविक भोजन में अखंडता और प्रामाणिकता का महत्व और तेजी से प्रामाणिकता परीक्षण के लिए विश्लेषणात्मक मापदंडों का विकास चर्चा के अन्य प्रमुख बिंदु थे।

'खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य पर पशु आहार का प्रभाव' विषय पर सत्र के दौरान, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद, भारत के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह ने अच्छी गुणवत्ता वाले चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने और पशु आहार के लिए मजबूत विनियमन की आवश्यकता पर जोर दिया, जो न केवल स्वस्थ पशुधन सुनिश्चित करेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि पशु मूल का भोजन मनुष्यों के लिए सुरक्षित है। अपने मुख्य भाषण में, प्रोफेसर एंड्रियास हेंसल, अध्यक्ष, बीएफआर, जर्मनी ने कहा, "ट्रेसेबिलिटी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ है"। उन्होंने बेहतर फ़ीड सुरक्षा के लिए ट्रेसेबिलिटी स्थापित करने के लिए बीएफआर, जर्मनी द्वारा विकसित उपकरणों पर भी प्रकाश डाला।

'खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य पर पशु आहार का प्रभाव' पर पैनल चर्चा का संचालन पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव सुश्री अलका उपाध्याय ने किया। इसमें कच्चे अवयवों और चारा योजकों सहित पशु आहार की सुरक्षा के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया। विशेषज्ञों ने पशु आहार के लिए प्रभावी ट्रेसेबिलिटी तंत्र पर अनिवार्य नियमों और राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता पर चर्चा की। पैनलिस्टों ने फ़ीड सुरक्षा की निगरानी के लिए नवीन दृष्टिकोण तलाशने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। सत्र का उद्देश्य जोखिम मूल्यांकन रणनीतियों में अंतर्दृष्टि विकसित करना और पशु चारा और उसके कच्चे अवयवों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए नीतियां तैयार करना है। कच्चे माल सहित पशु आहार की हैंडलिंग और भंडारण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय नीति/दिशानिर्देश विकसित करने, इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और रोगाणुरोधी और अन्य पशु चिकित्सा दवाओं के विकल्प के रूप में जातीय-पशु चिकित्सा दवाओं (ईवीएम) के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई।

इसके अलावा, शिखर सम्मेलन 'खाद्य आपातकालीन प्रतिक्रिया, स्मरण और विश्लेषण में नवाचार' पर एक सत्र के साथ आगे बढ़ा। इस सत्र ने खाद्य सुरक्षा के बारे में बढ़ती उपभोक्ता चिंताओं के जवाब में खाद्य विश्लेषण और तकनीकों में नवाचार के क्रांतिकारी प्रभाव को रेखांकित किया। मुख्य आकर्षणों में से एक मजबूत ट्रेसेबिलिटी सिस्टम स्थापित करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना था। ये प्रणालियाँ खाद्य उत्पादों को खेत में उनके मूल स्थान से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक प्रभावी ढंग से ट्रैक करती हैं, जिससे सुरक्षा संबंधी मुद्दों के मामले में कुशल और समय पर वापसी प्रक्रियाओं की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, सत्र ने खाद्य स्मरण और विश्लेषण में डिजिटल परिवर्तन के एक नए युग के उद्भव पर प्रकाश डाला, जिससे वास्तविक समय की खाद्य सुरक्षा निगरानी में क्रांति आ गई। पैनलिस्टों ने खाद्य सुरक्षा आकलन की दक्षता और सटीकता बढ़ाने में सहायक विश्लेषण के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के एकीकरण के बारे में चर्चा की। विचार-विमर्श में खाद्य आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए मजबूत निर्णय लेने वाले मंच की स्थापना के लिए पैटर्न की पहचान करने और संभावित जोखिमों का पता लगाने के लिए पूरी तरह से सत्यापन के बाद नियामक उद्देश्य के लिए त्वरित विश्लेषणात्मक किट के उपयोग और

बिग डेटा एनालिटिक्स के उपयोग पर भी जोर दिया गया।

इन सत्रों के दौरान साझा की गई अंतर्दृष्टि और अनुभव वैश्विक खाद्य सुरक्षा पहल को आगे बढ़ाने में अमूल्य हैं। विभिन्न देशों के नियामकों और विशेषज्ञों को एक साथ लाकर, जीएफआरएस 2023 ने खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और एएमआर, एंटीबायोटिक अवशेष, पशु फ़ीड को विनियमित करने, खाद्य उत्पादों के विश्लेषण आदि जैसी चुनौतियों से निपटने में समन्वित प्रयासों के लिए एक ठोस आधार तैयार किया है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग, ज्ञान साझाकरण और क्रॉस-लर्निंग को बढ़ावा देने के साथ-साथ एक सुरक्षित और अधिक टिकाऊ वैश्विक खाद्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

जीएफआरएस 2023 की पृष्ठभूमि

20 जुलाई, 2023 को माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया द्वारा उद्घाटन किए गए वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन ने खाद्य सुरक्षा प्रणालियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर दृष्टिकोण और ज्ञान का आदान-प्रदान करने के लिए दुनिया भर के खाद्य नियामकों को एक साथ लाया। फूड-ओ-कोपिया, खाद्य श्रेणी-वार मोनोग्राफ का संग्रह और किसी विशिष्ट उत्पाद के लिए सभी लागू मानकों के लिए एकल बिंदु संदर्भ सहित विभिन्न पहल; 'संग्रह' - राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन: उद्घाटन समारोह के दौरान वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण पुस्तिका और एक सामान्य डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया गया।
